मध्य प्रदेश राज्य

बनाम

सुरेंद्र कोरी

(आपराधिक अपील संख्या 1508 2012)

सितम्बर 26, 2012

[के.एस. राधाकृष्नन और दीपक मिश्रा जेजे.]

आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1973:

धारा 482- उच्च न्यायालय द्वारा अंतर्निहित शक्ति का प्रयोग व्याख्या की।

धारा 482 के तहत दंडनीय अपराधों के लिए उत्तरदाताओं के खिलाफ एफआईआर को रद्द करने की मांग वाली याचिका। 420, 467, 468, 471 संपठित धारा 34 और 120B IPC और धारा 34 और 81 पंजीकरण अधिनियम- सरदार सरोवर परियोजना के विस्थापितों के लिए विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ उठाने के लिए फर्जी दस्तावेजों पर फर्जी बिक्री कार्यों के पंजीकरण का आरोप- उच्च न्यायालय द्वारा एफआईआर को खारिज कर दिया गया: प्रतिवादी प्रासंगिक अवधि के दौरान उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा था, जब एक ही लेनदेन से संबंधित 102 से अधिक बिक्री कार्य निष्पादित किए गए थे और उन सभी दस्तावेजों को

प्रथम दृष्टया जाली पाया गया था ताकि लाभ प्राप्त किया जा सके। पैकेज जो परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों/भूमि से विस्थापित लोगों के लिए था - प्रतिवादी पर आरोप लगाया गया था कि उसने खरीददारों और विक्रेताओं की साख की पुष्टि किए बिना और बिक्री कार्यों के अंतर्गत आने वाली भूमि की जांच किए बिना परियोजना से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत किया था। अस्तित्व में थी या नहीं या भूमि राज्य सरकार की थी इसके अलावा यह देखा गया कि कुछ भूमियों के संबंध में कुछ कार्य निष्पादित किए गए थे जो पूरी तरह से उसके अपने उप-जिलों में स्थित नहीं थे और पंजीकरण अधिनियम की धारा 64 के प्रावधानों के अनुसार इसका पालन नहीं किया गया-प्रथम दृष्टया यह पाया गया कि विक्रेता और विक्रेता परियोजना प्रभावित व्यक्ति/विस्थापित नहीं थे, बल्कि वे पैकेज का लाभ उठाना चाहते थे, और इस तरह राज्य सरकार के साथ-साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापितों को धोखा दिया - प्रतिवादी को यह देखते हुए सेवा से निलंबित कर दिया गया कि वह भी अपराध के कमीशन में सहायक और उकसाया गया था - आरोप है कि जाली बिक्री कार्यों को गैरकानूनी लाभ के लिए निष्पादित किया गया था जिसके लिए प्रतिवादी ने भी साजिश रची है और अपराध को बढ़ावा दिया है - अपराध की भयावहता को देखते हुए, धोखाधड़ी से निष्पादित किए गए कथित दस्तावेजों की संख्या, आरोप-पत्रों में संदर्भित रिपोर्ट और प्रतिवादी की संलिप्तता आदि को ध्यान में रखा जा सकता है। केवल तभी निर्णय लिया जा सकता है जब

अभियोजन को अवसर दिया गया हो - उच्च न्यायालय, ऐसी परिस्थितियों में, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्रों को रद्द करना उचित नहीं था। 482- उच्च न्यायालय के निर्णय निरस्त किये जाते हैं।

एम.एम.टी.सी. लिमिटेड और अन्य. बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड और अन्य। 2001 (5) सप्ल. एससीआर 265=2002 (1) एससीसी 234; उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सरोज कुमार साहू 2005 (5) सप्ल। एससीआर 548 =(2005) 13 एससीसी 540 और आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाम हरिहर सिंह (2006) 12 एससीसी 763 पर भरोसा किया।

जम्बू प्रसाद बनाम मोहम्मद नवाब आफताब अली खान एआईआर 1941 पीसी 16 का उल्लेख है।

केस कानून संदर्भ:

2001 (5) सप्ल. एससीआर 265 का अवलम्ब लिया
पैरा 13

2005 (5) पूरक। एससीआर 548 का अवलम्ब लिया
पैरा 13

(2006) 12 एससीसी 763 का अवलम्ब लिया
पैरा 13

एआईआर 1941 पीसी 16 करने के लिए भेजा पैरा 16

आपराधिक अपीलीय क्षेत्राधिकार: आपराधिक अपील संख्या 1508/2012।

मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, इंदौर की जबलपुर खंडपीठ के 2008 के विविध आपराधिक मामले संख्या 1073 द्वारा अंतिम निर्णय व आदेश दिनांकित 22.01.2009 से उत्पन्न।

साथ

सीए। क्रमांक 1509, 1510, 1511, 1512, 1513, 1514, 1515, 1516, 1517, 1518, 1519, 1520, 1521, 1522, 1523, 1524, 1525, 1526, 1527, 1528, 1529, 1530, 1531, 1532, 1533, 1534, 1535, 1536, 1537, 3538, 1539, 1540, 1541, 1542, 1543, 1544, 1545, 1546, 1 547, 1548, 1549, 1550, 1551, 2012 के 1552, 1553, 1554, 1555, 1556, 1557, 1558, 1559, 1560 और 1561।

सिद्धार्थ दवे, अभिमन्यु सिंह, सी.डी. सिंह अपीलार्थी की ओर से।

प्रतिवादी की ओर से अर्धेन्दुमौली कुमार प्रसाद।

न्यायालय का निम्नलिखित आदेश सुनाया गया

आदेश

1. छुट्टी स्वीकृत.

2. दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना।

3. हम इन सभी चौवन अपीलों का निपटान एक सामान्य आदेश द्वारा कर रहे हैं क्योंकि इन सभी अपीलों में विचार के लिए समान मुद्दे सामने आते हैं। इन अपीलों के निपटान के उद्देश्य से, हम 2010 की एसएलपी (सीआरएल) संख्या 3149 से उत्पन्न आपराधिक अपील में तथ्यों का उल्लेख कर सकते हैं, इसे प्रमुख मामला मानते हुए।

4. यहां प्रतिवादी, जो उप रजिस्ट्रार, खरगोन के रूप में कार्य कर रहा था, पर भारतीय दंड संहिता की धारा 420, 467, 468, 471 के साथ धारा 34 और 120 बी (संक्षेप में 'आईपीसी') के तहत दंडनीय अपराधों के लिए आरोप पत्र दायर किया गया था। और पंजीकरण अधिनियम की धारा 34 और 81 के तहत। मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर खंडपीठ ने दंड प्रक्रिया संहिता (संक्षेप में 'सीआरपीसी') की धारा 482 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रतिवादी के खिलाफ दायर प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप पत्र को भी रद्द कर दिया। 2007 का आपराधिक मामला संख्या 2500 और अन्य जुड़े हुए मामले. उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेशों की सत्यता या अन्यथा की उचित सराहना करने के लिए, कुछ तथ्यों का उल्लेख करना आवश्यक है।

5. मध्य प्रदेश राज्य ने उन व्यक्तियों के लिए एक विशेष पुनर्वास पैकेज (संक्षेप में 'पैकेज') पेश किया था, जो सरदार सरोवर परियोजना (संक्षेप में 'परियोजना') को लागू करते समय जलमग्न अपनी भूमि से विस्थापित हो गए थे। पैकेज के अनुसार, परियोजना से प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापितों को दो किस्तों में नकद लाभ प्रदान किया गया ताकि वे अपनी पसंद की भूमि खरीद सकें। राशि विस्थापितों के बैंक खातों में जमा की जाएगी और पहली किस्त तब जारी की जाएगी जब विस्थापित जमीन खरीदने का शपथ पत्र जमा करेंगे और दूसरी और अंतिम किस्त तब जारी की जाएगी जब विक्रेता और खरीदार दोनों अपना विक्रय पत्र पंजीकृत करा लेंगे। और विक्रय विलेख के ऐसे पंजीकरण का प्रमाण प्रस्तुत करें। यह आरोप लगाया गया था कि उस पैकेज का लाभ उठाने के लिए खरगोन में रजिस्ट्रार कार्यालय में विभिन्न फर्जी विक्रय पत्र पंजीकृत कराए गए थे। जिस तरीके से पैकेज का लाभ उन व्यक्तियों द्वारा उठाया गया जो परियोजना से प्रभावित नहीं थे, इसके बारे में शिकायतें उठाई गईं। नर्मदा बचाओ आंदोलन ने पैकेज के लाभ का दावा करने के लिए फर्जी विक्रय पत्रों के पंजीकरण के संबंध में नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण के समक्ष एक शिकायत भी दर्ज की।

6. कलेक्टर, जिला खरगोन ने अपने पत्र दिनांक 23.7.2007 द्वारा डिप्टी कलेक्टर, खरगोन को जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिये।

उपजिलाधिकारी ने 11.9.2007 को रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

> "चूंकि इन बिक्री लेनदेन की विस्तृत जांच पुलिस कार्रवाई के बिना संभव नहीं लगती है, इसलिए आपराधिक मामला दर्ज किया जा रहा है और विस्तृत जांच के बाद दोषी व्यक्तियों को सजा देने की कार्यवाही के लिए इस प्रारंभिक जांच रिपोर्ट को नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को
>
> भेजा जा रहा है।" मामला मिल रहा है संबंधित जिले के कलेक्टर के माध्यम से भूमि अधिग्रहण अधिकारी द्वारा पुलिस कार्रवाई के लिए पंजीकरण प्रस्तावित है।"

इसके अलावा, कई बिक्री कार्यों का जिक्र करते हुए, यह विशेष रूप से बताया गया था कि दस्तावेजों के कुछ विक्रेता और विक्रेता फर्जी व्यक्ति थे और कार्यों को धोखाधड़ी से निष्पादित और पंजीकृत किया गया था।

7. परियोजना के पुनर्वास अधिकारी, जिला खरगोन द्वारा कोतवाली थाने में दर्ज कराई गई शिकायतों पर कई एफआईआर दर्ज की गईं। एफआईआर संख्या 496 दिनांक 18.9.2007 में डिप्टी कलेक्टर की दिनांक 11.9.2007 की रिपोर्ट का विशेष रूप से उल्लेख किया गया था। एफआईआर का ऑपरेटिव भाग इस प्रकार है:

"12.....संदर्भः- कलेक्टर खरगोन का पत्र क्रमांक 791 दिनांक 11.9.2007 आवश्यक कार्यवाही हेतु प्राप्त हुआ। उपरोक्त विषय में बताया गया है कि नाम विस्थापित (वेंडी) नानिया हरिया पुत्र गांगली को पंजीयन क्रमांक ए-1/2575 दिनांक 25/3/2006 जमा करने पर विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में 3,39,857/- रूपये की राशि प्राप्त हुई है। अपर कलेक्टर, खरगोन ने पाया है उक्त पंजीयन की जांच में यह पाया गया कि विक्रय पत्र में सर्वे क्रमांक गलत है। विक्रेता न तो गांव का निवासी है और न ही विक्रेता का गांव में कोई अस्तित्व है। अतः प्रथम दृष्टया विक्रय लेनदेन होना पाया गया है। अवैध हो। इस संबंध में विक्रेता अमर सिंह पुत्र चंदर सिंह जाति-राजपूत, निवासी बम्हनाला एवं गवाहों (1) आशिक पुत्र के साथ सहमति बनाकर षडयंत्रपूर्वक उक्त फर्जी पंजीयन तैयार कर विक्रेता द्वारा प्रस्तुत किया गया है। /ओ अलबली पिंजारा, निवासी सोंदुल जिला बारबानी (2) जगदीश पुत्र पाटलिया निवासी देहडाला और टावर खगोन के पास डीड राइटर बी.एल. गुप्ता, रवींद्र नगर बाहेती के साथ अनुचित और अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से भूमि खसरा नं. 76 ग्राम पोखरबुजुर्ग, तहसील भिखंगौण, जिला।

खरगोन. पर उक्त फर्जी पंजीकरण के आधार पर उसने सरकार को अनुचित रूप से 3,39,857/- रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाकर अपराध किया है। इसलिए प्रतिवादी नानिया पुत्र हरिया निवासी गांगली, तहसील मनावर जिला के विरुद्ध आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाए। धार, विक्रेता अमर सिंह पुत्र चंदर सिंह जाति राजपूत, निवासी बम्हनाला और गवाहों के खिलाफ (1) आशिक पुत्र अलबली पिंजारा, निवासी सोंदुल जिला। - बारबनी (2) जगदीश पुत्र पतलिया निवासी देहडाला और डीड राइटर बी.एल. गुप्ता, रवीन्द्र नगर बाहेती टावर के पास खरगोन। उप पंजीयक कार्यालय खरगोन में फर्जी पंजीयन के संबंध में रिपोर्ट प्रस्तुत की गई है।

अनुलग्नक:-

1. पत्र क्रमांक. 791 दिनांक 11/9/07 कलेक्टर खरगोन जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति सहित।

2. रजिस्ट्रेशन नंबर की फोटोकॉपी. ए-1/2575 दिनांक 25/3/2006 हस्ताक्षर अशोक कुमार मोदी, पुनर्वास अधिकारी, सरदार सरोबर परियोजना, मनबाज, जिला धार.

13. उपरोक्त विवरण के संबंध में धारा 420, 467, 468, 469, 471, 34 के तहत कार्यवाही की गई। प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया/नहीं लिया गया तथा प्रकरण ओम प्रकाश मिश्रा (निरीक्षक) को सौंपा गया /उपनिरीक्षक) या क्षेत्राधिकार के आलोक में इसे पी.एस.डी.सी. में स्थानांतरित कर दिया गया था।"

8. हमने पाया कि मध्य प्रदेश राज्य के पंजीकरण विभाग को 1.4.2005 और 31.3.2007 के बीच बड़े पैमाने पर बिक्री कार्यों के पंजीकरण के बारे में पता चलने के बाद, प्रतिवादी को खड़ा करके जांच के आदेश भी दिए गए थे। उप पंजीयक, खरगोन को संबंधित समय पर निलंबित कर दिया गया है। जिला रजिस्ट्रार, खरगोन द्वारा विस्तृत जांच की गई और उन्होंने 27.10.2007 को महानिरीक्षक को रिपोर्ट सौंपी (पंजीकरण), मध्य प्रदेश राज्य। पूछताछ में निम्नलिखित प्रक्रियात्मक अनियमितताएँ पाई गईं:

"1. पांच वर्ष के खसरा की नकल की फोटोकॉपी भी मान्य की गई है। विस्तृत विवरण संलग्न सूची में अंकित है।

2. पंजीकरण अधिनियम की धारा 30(1) के तहत उप रजिस्ट्रार, मुख्यालय को संबंधित कार्यों के पंजीकरण में

पंजीकरण शुल्क तालिका के अनुच्छेद -7 के तहत 200/- रुपये का अतिरिक्त शुल्क नहीं मिला है। जिले की अन्य तहसीलों में स्थित सम्पत्ति को उक्त सारणी के अनुच्छेद- 10 के अन्तर्गत रू.10/- रू.

3. पंजीयन अधिनियम 1908 की धारा-30(1) के अंतर्गत उप पंजीयक, मुख्यालय द्वारा उक्त अधिनियम की धारा-64 के अंतर्गत संबंधित उप पंजीयकों को संबंधित विलेखों के पंजीयन हेतु मेमो नहीं भेजा गया है। जिले की अन्य तहसीलों में स्थित संपत्तियां।

4. महानिरीक्षक-पंजीकरण के परिपत्र संख्या 2822/तक/एक/2005 दिनांक 21.11.2005 के अनुपालन में कृषि भूमि से संबंधित विलेखों में शपथ पत्र दाखिल नहीं किया गया है; भोपाल. विस्तृत विवरण संलग्न सूची में उपलब्ध है।

5. महानिरीक्षक पंजीयन भोपाल के परिपत्र क्रमांक 3610/तक/एक/2004 दिनांक 15.12.04 के अनुसार पी.ए.एन. कार्ड नं. रुपये के मूल्यांकन के कार्यों के पंजीकरण के समय विक्रेताओं और वेंडरों का उल्लेख नहीं

किया गया है। आयकर अधिनियम 1961 की धारा 139ए और उसके तहत बनाए गए नियम 114 ख और 114 घ के प्रावधानों के अनुसार पांच लाख या उससे अधिक। उप पंजीयक खरगोन से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 26.10.2007 के अनुसार ड्राफ्ट क्रमांक 60 एवं 61 प्राप्त नहीं हुए हैं। संबंधित कार्यों का उल्लेख संलग्न सूची में किया गया है।

6. विलेखों में प्रमाण पत्रों की फोटो प्रतियां इसके स्थान पर भू-अर्जन पदाधिकारी को स्वीकार कर लिया गया है मूल, जिसका विवरण संलग्नक सूची में दिया गया है

7. ऋण पुस्तिका के संबंध में जानकारी दी गई है संलग्न सूची में दिखाया गया है।"

9. जांच अधिकारी ने उपरोक्त उल्लिखित रिपोर्टों पर ध्यान दिया और सीआरपीसी की धारा 173(8) के तहत एक अंतिम रिपोर्ट (चार्ज-शीट संख्या 546, 2007) प्रस्तुत की गई। अदालत के समक्ष प्रतिवादी के खिलाफ और उन व्यक्तियों के खिलाफ भी, जिन्होंने 25.3.2006 को बिक्री विलेख निष्पादित करवाया था और आईपीसी की धारा 34 और 120-बी के साथ पढ़ी जाने वाली धारा 420, 467, 468, 469, 471 के तहत आरोप लगाया

गया था। पंजीकरण अधिनियम, 1908 की धारा 34 और 81। आरोप-पत्र का सक्रिय भाग इस प्रकार है:

"घटना का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि दिनांक 18/9/07 को एक लिखित प्रार्थना पत्र जांच हेतु विलेख सहित लाकर प्रस्तुत किया गया। नानिया पुत्र हरिया निवासी गांगली को 339857/ रूपये की राशि प्राप्त हुई। - विशेष पुनर्वास अनुदान के रूप में पंजीयन क्रमांक ए-1/2575 दिनांक 25/5/3006 प्रस्तुत कर उक्त रजिस्ट्री की जांच में अपर कलेक्टर, खरगौन द्वारा यह पाया गया कि विक्रय पत्र का सर्वे क्रमांक गलत है। विक्रेता गांव का निवासी नहीं है और न ही विक्रेता का गांव में कोई अस्तित्व है। अतः प्रथम दृष्टया ही विक्रय लेनदेन अवैध पाया गया। इस संबंध में विक्रेता द्वारा फर्जी तरीके से उक्त फर्जी पंजीयन तैयार कर प्रस्तुत किया गया है। विक्रेता अमर सिंह पुत्र चंदर सिंह जाति-राजपूत, निवासी बम्हनाला और गवाहों (1) आशिक पुत्र अलबली पिंजारा, निवासी सोंदुल जिला बारबानी (2) जगदीश पुत्र के साथ सहमति के बाद साजिश रची। ओ पतलिया निवासी देहदला और बैनामा के साथ बी.एल.गुप्ता, रवीन्द्र नगर बाहेती टावर खरगोन के पास खसरा नंबर की भूमि से

अनुचित एवं अवैध लाभ प्राप्त करने के उद्देश्य से लिखें। 76 ग्राम पोखरबुजुर्ग, तहसील भिखंगौण, जिला। खरगोन. पर उक्त फर्जी पंजीकरण के आधार पर उसने सरकार को अनुचित रूप से 339857/- रुपये की वित्तीय हानि पहुंचाकर अपराध किया है। मामले में आरोपी बी.एल. गुप्ता और सुरेंद्र कोरी को भी गिरफ्तार किया गया है. प्रकरण में आरोपी बी.एल. के संबंध में बैंक का दस्तावेज प्राप्त होना

एवं आरोपी नानिया के अंगूठे के निशान के मिलान की कार्यवाही शेष है। गुप्त साक्ष्य एकत्रित करना है। आरोपी सुरेंद्र कोरी के संबंध में प्रमाणित हस्तलेखन परीक्षण रिपोर्ट एवं आवश्यक दस्तावेज एवं जिला पंजीयक का कथन लिया जाना है। आरोपी सुरेंद्र कोरी ने अपराध में

आपराधिक षडयंत्र का अपराध कारित करने में सहयोग किया है तथा अपने पद का दुरुपयोग किया है। इस संबंध में भी जांच की जा रही है और आरोपियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल करने की अनुमति मांगी जा रही है. इस मामले में उंगलियों के निशान का मिलान और बाकी

आरोपियों की गिरफ्तारी की जानी है. अभी अपर कलेक्टर खरगोन की जांच रिपोर्ट और उनका बयान लिया जाना बाकी है। अब तक की कोशिशों के बावजूद इन्हें

अब तक आगे नहीं बढ़ाया जा सका है. इस मामले में आरोपी नानिया के विरूद्ध धारा 173(8) के तहत आरोप पत्र 546/07 तैयार कर अपराध पुष्ट पाये जाने पर अभी तक अपराध प्रस्तुत नहीं किया गया है। मामले में अभी जांच चल रही है, जिसके खत्म होने के बाद पूरी चार्जशीट अलग से दाखिल की जाएगी."

10. इसके बाद प्रतिवादी ने एफआईआर के साथ-साथ उसके खिलाफ दायर विभिन्न आरोप-पत्रों को रद्द करने के लिए उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया। उच्च न्यायालय के समक्ष यह तर्क दिया गया कि प्रतिवादी, पंजीकरण अधिनियम के तहत, उप-रजिस्ट्रार की क्षमता में बिक्री कार्यों को पंजीकृत करने के लिए बाध्य है। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि पंजीकरण के लिए उनके सामने लाए गए दस्तावेजों की शुद्धता या वास्तविकता के बारे में पता लगाने का उनका कोई दायित्व या कर्तव्य नहीं था। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि प्रतिवादी के पास नहीं था कथित जालसाजी या फर्जी तरीके के बारे में जानकारी जिसमें बिक्री कार्यों को पंजीकृत करने की मांग की गई थी। राज्य की ओर से उपस्थित उप शासकीय अधिवक्ता ने तर्क दिया कि जिला रजिस्ट्रार, खरगोन के माध्यम से एक विस्तृत जांच करने के बाद यह पाया गया कि प्रतिवादी भी धोखाधड़ी वाले लेनदेन में शामिल था और उसने उन बिक्री कार्यों को निष्पादित करने में पार्टियों को परेशान किया था।

11. उच्च न्यायालय ने यह विचार किया कि प्रतिवादी, उप-रजिस्ट्रार की क्षमता में और पंजीकरण अधिनियम के तहत कार्य करते हुए, अपने सामने लाए गए दस्तावेजों को पंजीकृत करने के लिए बाध्य था और उससे शीर्षक की शुद्धता और वास्तविकता के बारे में पता लगाने की उम्मीद नहीं की गई थी। संपत्ति का और यह भी कि क्या उन बिक्री कार्यों को निष्पादित करने में विक्रेताओं और विक्रेताओं के बीच कोई साजिश थी। इसके अलावा, यह भी बताया गया कि जांच रिपोर्ट से पता चला कि बिक्री कार्यों के पंजीकरण में केवल प्रक्रियात्मक अनियमितताएं थीं और उन बिक्री कार्यों को निष्पादित करने में प्रतिवादी की भागीदारी दिखाने के लिए कुछ भी नहीं था। न्यायालय ने माना कि पंजीकरण अधिनियम की धारा 34 के प्रावधानों के आधार पर, प्रतिवादी को इस आधार पर उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता है कि उसने कथित तौर पर बेची गई संपत्ति के विक्रेता के शीर्षक को सत्यापित नहीं किया था। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत प्रदत्त अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पुनरीक्षण याचिकाओं को स्वीकार कर लिया और सभी मामलों में प्रतिवादी के खिलाफ दायर एफआईआर और आरोप-पत्रों को रद्द कर दिया और उसके खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों को रद्द कर दिया। . उसी से व्यथित होकर, ये आपराधिक अपीलें राज्य द्वारा दायर की गई हैं।

12. राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वकील श्री सिद्धार्थ दवे ने प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय ने यह मानने में त्रुटि की है कि रजिस्ट्रार

का कर्तव्य केवल बिक्री कार्यों को पंजीकृत करना है। विद्वान वकील ने आगे कहा कि, किसी दिए गए मामले में, यदि यह प्रथम दृष्टया स्थापित है, तो रजिस्ट्रार फर्जी व्यक्तियों द्वारा कई बिक्री कार्यों के निष्पादन में सहायता करने में भी सहायक है, ताकि पैकेज के तहत लाभ को उचित ठहराया जा सके, जिसके परिणामस्वरूप राज्य को नुकसान हो सकता है। राजकोष, वह भी है

यदि अपराध करने में उकसाया गया पाया गया तो उत्तरदायी होगा। विद्वान वकील ने बताया कि जिला कलेक्टर और पंजीकरण विभाग के रजिस्ट्रार द्वारा विस्तृत जांच करने के बाद प्रतिवादी के खिलाफ आरोप लगाए गए थे। विद्वान वकील ने बताया कि इतनी बड़ी संख्या में बिक्री कार्य प्रतिवादी की जानकारी या सक्रिय मिलीभगत के बिना निष्पादित नहीं किए जा सकते थे। प्रतिवादी की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने कहा कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश में कोई अवैधता नहीं है जो इन अपीलों में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप की मांग करता है।

13. उच्च न्यायालय सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए अपील या पुनरीक्षण न्यायालय के रूप में कार्य नहीं करता है। इस न्यायालय ने कई निर्णयों में कहा है कि सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार, हालांकि व्यापक है, इसका उपयोग संयमित, सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना

चाहिए। सीआरपीसी की धारा 482 के तहत उच्च न्यायालय को आम तौर पर ऐसे मामले में प्रथम दृष्टया निर्णय देने से बचना चाहिए जहां सभी तथ्य अधूरे और धुंधले हों, खासकर तब जब साक्ष्य एकत्र नहीं किए गए हों और अदालत के समक्ष पेश नहीं किए गए हों और इसमें शामिल मुद्दे हों। तथ्यात्मक या कानूनी, व्यापक परिमाण के होते हैं और पर्याप्त सामग्री के बिना उन्हें उनके वास्तविक परिप्रेक्ष्य में नहीं देखा जा सकता है। एम.एम.टी.सी. में और अन्य बनाम मेडचल केमिकल्स एंड फार्मा (पी) लिमिटेड और अन्य (2002) 1 एससीसी 234, इस न्यायालय ने इस प्रकार माना:

> "कानून अच्छी तरह से स्थापित है कि आपराधिक कार्यवाही को रद्द करने की शक्ति का प्रयोग बहुत सख्ती से और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए। यह स्थापित कानून है कि इस स्तर पर, न्यायालय की विश्वसनीयता या वास्तविकता या अन्यथा के बारे में जांच शुरू करना उचित नहीं है। शिकायत में लगाए गए आरोप। अंतर्निहित शक्तियां न्यायालय को अपनी इच्छा या इच्छा के अनुसार कार्य करने का मनमाना क्षेत्राधिकार प्रदान नहीं करतीं..."

उड़ीसा राज्य और अन्य बनाम सरोज कुमार साहू (2005) 13 एससीसी 540 में, इस न्यायालय ने इस प्रकार निर्णय दिया:

"सीआरपीसी की धारा 482 के तहत शक्ति का प्रयोग।"

इस प्रकृति के मामले में अपवाद है, नियम नहीं। यह धारा उच्च न्यायालय को कोई नई शक्तियाँ प्रदान नहीं करती है। यह केवल उस अंतर्निहित शक्ति को बचाता है जो सीआरपीसी के अधिनियमन से पहले न्यायालय के पास थी। इसमें तीन परिस्थितियों की परिकल्पना की गई है जिनके तहत अंतर्निहित क्षेत्राधिकार का प्रयोग किया जा सकता है, अर्थात्, (i) सीआरपीसी के तहत एक आदेश को प्रभावी करने के लिए, (ii) अदालत की प्रक्रिया के दुरुपयोग को रोकने के लिए, और (iii) अन्यथा सुरक्षित करने के लिए। न्याय का अंत. किसी भी अनम्य नियम को निर्धारित करना न तो संभव है और न ही वांछनीय है जो अंतर्निहित क्षेत्राधिकार के अभ्यास को नियंत्रित करेगा। प्रक्रिया से संबंधित कोई भी विधायी अधिनियम संभवतः उत्पन्न होने वाले सभी मामलों के लिए प्रावधान नहीं कर सकता है। इसलिए, अदालतों के पास कानून के स्पष्ट प्रावधानों के अलावा अंतर्निहित शक्तियां हैं जो कानून द्वारा उन पर लगाए गए कार्यों और कर्तव्यों के उचित निर्वहन के लिए आवश्यक हैं। यह वह सिद्धांत है जो उस

अनुभाग में अभिव्यक्ति पाता है जो केवल उच्च न्यायालयों की अंतर्निहित शक्तियों को पहचानता है और संरक्षित करता है। सभी अदालतें, चाहे वे दीवानी हों या फौजदारी, उनके संविधान में निहित किसी स्पष्ट प्रावधान के अभाव में, "क्वांडो लेक्स" के सिद्धांत पर न्याय प्रशासन के दौरान सही करने और गलत को ठीक करने के लिए आवश्यक सभी शक्तियां रखती हैं। अलियाउइड एलिकुई कॉन्सेडिट, कन्सीडर्ड विडेटुर एट आईडी साइन गुओ रिसिप्से एस्से नॉन पोटेस्ट" (जब कानून किसी व्यक्ति को कुछ भी देता है तो यह उसे वह देता है जिसके बिना उसका अस्तित्व नहीं हो सकता)। धारा के तहत शक्तियों का प्रयोग करते समय, अदालत अपील या पुनरीक्षण अदालत के रूप में कार्य नहीं करती है। इस धारा के तहत निहित अधिकार क्षेत्र का प्रयोग हालांकि व्यापक रूप से किया जाना चाहिए, लेकिन इसका उपयोग सावधानी से, सावधानीपूर्वक और सावधानी के साथ किया जाना चाहिए और केवल तभी जब ऐसा प्रयोग धारा में विशेष रूप से निर्धारित परीक्षणों द्वारा उचित हो..."

यह न्यायालय, फिर से, आयशर ट्रैक्टर्स लिमिटेड बनाम हरिहर सिंह (2006) 12 एससीसी 763 में, इस प्रकार आयोजित किया गया:

"धारा 482 के तहत क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते समय संहिता के अनुसार, उच्च न्यायालय आम तौर पर कोई कार्यवाही शुरू नहीं करेगाजांच करें कि क्या विचाराधीन साक्ष्य विश्वसनीय है या नहीं या क्या इसकी उचित सराहना करने पर आरोप टिक नहीं पाएगा। यह ट्रायल जज का कार्य है।"

14. हमारा विचार है कि उपर्युक्त निर्णयों में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित सिद्धांत वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर पूरी तरह लागू होंगे। इन मामलों में हम कई फर्जी बिक्री कार्यों के निष्पादन से संबंधित हैं जिनका उद्देश्य गैरकानूनी लाभ कमाना था। जैसा कि पहले ही संकेत दिया गया है, विशेष पुनर्वास परियोजना विस्थापितों और परियोजना प्रभावित परिवारों को नकद मुआवजा देने के लिए शुरू की गई थी, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात से जुड़े चार राज्यों की एक अंतर-राज्यीय परियोजना है। पुनर्वास और पुनर्स्थापन नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण (एनडब्ल्यूबीटी) पुरस्कार द्वारा शासित होता है। यह आरोप लगाया गया था कि प्रतिवादी ने क्रेता और विक्रेता की साख की पुष्टि किए बिना और यह जांच किए बिना कि बिक्री कार्यों के अंतर्गत आने वाली भूमि अस्तित्व में है या नहीं या भूमि राज्य सरकार की है, परियोजना से संबंधित विभिन्न दस्तावेजों को पंजीकृत किया। बताया गया कि रजिस्ट्रार कार्यालय ने एक ओ.एम. जारी किया था। दिनांक 28.4.2005 को सभी

उप-रजिस्ट्रारों को यह कहते हुए भेजा गया कि नकली बिक्री कार्यों के पंजीकरण को रोकने के लिए बिक्री कार्यों को पंजीकृत करते समय विक्रेता की पहचान को सत्यापित करने के लिए विक्रेता से फोटो पहचान प्रमाण जैसे पैन कार्ड मांगना होगा। या पासपोर्ट, जो नहीं बनाया गया था। इसके अलावा यह देखा गया कि कुछ भूमियों के संबंध में कुछ कार्य निष्पादित किए गए थे जो पूरी तरह से उनके अपने उप-जिलों में स्थित नहीं थे और पंजीकरण अधिनियम की धारा 64 के प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था।

15. प्रतिवादी 1.4.2005 से 31.3.2007 की अवधि के दौरान खरगोन में उप रजिस्ट्रार के रूप में कार्य कर रहा था, जब एक ही लेनदेन से संबंधित 102 से अधिक बिक्री कार्य निष्पादित किए गए थे और वे सभी दस्तावेज प्रथम दृष्टया जाली पाए गए थे। उस पैकेज का लाभ प्राप्त करें जो परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापितों के लिए था भूमि से विस्थापित. प्रथम दृष्टया, यह देखा गया कि विक्रेता और विक्रेता परियोजना प्रभावित व्यक्ति/विस्थापित नहीं थे, लेकिन वे पैकेज का लाभ उठाना चाहते थे, जिससे राज्य सरकार के साथ-साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों/विस्थापितों को धोखा दिया गया। प्रतिवादी को यह देखते हुए सेवा से निलंबित कर दिया गया कि अपराध को अंजाम देने में उसकी भी भूमिका थी और उसे उकसाया गया था। आरोप-पत्रों में लगाए गए आरोप प्रथम दृष्टया आरोप हैं और मामले में सबूतों के आधार पर प्रतिवादी की

संलिप्तता के सवाल पर अंतिम निर्णय लिया जाना है और इस समय, हम केवल प्रथम सूचना रिपोर्ट में उठाए गए संकेतों से चिंतित हैं। और आरोप पत्र. आरोप यह है कि जाली विक्रय पत्र गैरकानूनी लाभ के लिए निष्पादित किए गए थे, जिसके लिए प्रतिवादी ने भी साजिश रची और अपराध को बढ़ावा दिया। इसके अलावा आरोप पत्र में पंजीकरण अधिनियम की धारा 34 का भी उल्लेख है जो इस प्रकार है:

34. पंजीकरण से पहले पंजीकरण अधिकारी द्वारा पूछताछ

(1) इस भाग और धारा 41, 43, 45, 69, 75, 77, 88 और 89 में निहित प्रावधानों के अधीन, कोई भी दस्तावेज़ इस अधिनियम के तहत पंजीकृत नहीं किया जाएगा, जब तक कि ऐसे दस्तावेज़ को निष्पादित करने वाला व्यक्ति, या उनके प्रतिनिधि, उपरोक्तानुसार अधिकृत

प्रतिनिधि या एजेंट, धारा 23, 24, 25 और 26 के तहत प्रस्तुति के लिए अनुमत समय के भीतर पंजीकरण अधिकारी के समक्ष उपस्थित हों:

बशर्ते कि, यदि तत्काल आवश्यकता या अपरिहार्य दुर्घटना के कारण ऐसे सभी व्यक्ति उपस्थित नहीं होते हैं, तो रजिस्ट्रार, ऐसे मामलों में जहां उपस्थित होने में देरी चार महीने से अधिक नहीं होती है, जुर्माने की राशि के दस गुना से अधिक नहीं भुगतान करने का निर्देश दे सकता है। उचित पंजीकरण शुल्क, धारा 25 के तहत देय जुर्माने के अलावा, यदि कोई हो, दस्तावेज़ पंजीकृत किया जा सकता है।

(2) उपधारा (1) के तहत उपस्थिति एक साथ या अलग-अलग समय पर हो सकती है।

(3) पंजीकरण अधिकारी तदुपरान्त-

(ए) पूछताछ करें कि क्या ऐसा दस्तावेज़ निष्पादित किया गया था या नहीं उस व्यक्ति द्वारा जिसके द्वारा इसे निष्पादित किया जाना तात्पर्यित है;

(बी) उसके सामने पेश होने वाले और यह आरोप लगाने वाले व्यक्तियों की पहचान के बारे में खुद को संतुष्ट करेगा कि उन्होंने दस्तावेज़ निष्पादित किया है; और

(सी) किसी भी व्यक्ति के प्रतिनिधि, समनुदेशिती या एजेंट के रूप में उपस्थित होने के मामले में, ऐसे व्यक्ति के उपस्थित होने के अधिकार के बारे में स्वयं को संतुष्ट करें।

(4) उप-धारा (1) के परंतुक के तहत निर्देश के लिए कोई भी आवेदन उप-रजिस्ट्रार के पास दर्ज किया जा सकता है, जो इसे तुरंत रजिस्ट्रार को भेज देगा जिसके वह अधीनस्थ है।

(5) इस धारा में कुछ भी डिक्री/आदेश की प्रतियों पर लागू नहीं होता है.

16. जम्बू प्रसाद बनाम मोहम्मद नवाब आफताब अली खान एआईआर 1941 पीसी 16 में कहा गया है कि इस धारा का उद्देश्य व्यक्तियों

के लिए अधिनियम के तहत पंजीकरण के माध्यम से धोखाधड़ी करना मुश्किल बनाना है। इसके अलावा साक्ष्य अधिनियम की धारा 114 के तहत एक धारणा है कि आधिकारिक कार्य पंजीकरण अधिनियम के तहत निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार किए गए हैं। इसलिए, जब किसी दस्तावेज़ को विधिवत निष्पादित किया गया है तो यह माना जाएगा कि इसे कानून के अनुसार पंजीकृत किया गया है और अभियोजन पक्ष पर यह दिखाने का दायित्व है कि प्रतिवादी ने अपराध में आपराधिक साजिश रचने के लिए उकसाया है और दुरुपयोग किया है उसकी स्थिति धोखाधड़ी में एक पक्ष थी।

17. पंजीकरण अधिनियम की धारा 81 दंड से संबंधित है जो इस प्रकार है:

> "81. हर किसी को नुकसान पहुंचाने के इरादे से दस्तावेजों का गलत तरीके से समर्थन, नकल, अनुवाद या पंजीकरण करने के लिए जुर्माना इस अधिनियम के तहत नियुक्त पंजीकरण अधिकारी और इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए उसके कार्यालय में कार्यरत प्रत्येक व्यक्ति, जिस पर इसके प्रावधानों के तहत प्रस्तुत या जमा किए गए किसी भी दस्तावेज़ का समर्थन करने, प्रतिलिपि बनाने, अनुवाद करने या पंजीकृत करने का आरोप लगाया गया है। ऐसे दस्तावेज़ को इस तरीके से जिसके बारे में वह

जानता है या विश्वास करता है कि वह गलत है, इसका इरादा इसके द्वारा किसी भी व्यक्ति को चोट पहुंचाने का इरादा है या यह जानते हुए कि वह इसके द्वारा चोट पहुंचा सकता है, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित के अनुसार, कारावास से दंडनीय होगा। जिसे सात साल तक बढ़ाया जा सकता है, या जुर्माना, या दोनों से दंडित किया जा सकता है।"

18. सवाल यह है कि क्या प्रतिवादी को पता था कि ऐसे कार्य गैरकानूनी लाभ प्राप्त करने के लिए निष्पादित किए गए थे, जिससे किसी अन्य व्यक्ति को चोट लग सकती है जैसा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 44 के तहत परिभाषित किया गया है, यह एक ऐसा मामला है जिसे केवल सबूत पेश करने पर ही स्थापित किया जा सकता है।

19. हमारी सुविचारित राय है कि अपराध की भयावहता को देखते हुए, धोखाधड़ी से निष्पादित किए गए कथित दस्तावेजों की संख्या, आरोप-पत्रों में संदर्भित रिपोर्ट और प्रतिवादी की संलिप्तता आदि के बारे में ही निर्णय लिया जा सकता है। यदि अभियोजन को अवसर दिया जाए। ऐसी परिस्थितियों में, उच्च न्यायालय द्वारा सीआरपीसी की धारा 482 के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए सभी प्रथम सूचना रिपोर्ट और आरोप-पत्रों को रद्द करना उचित नहीं था।

20. हम यह स्पष्ट करते हैं कि हमने ऊपर जो कुछ भी कहा है वह केवल प्रथम दृष्टया टिप्पणियाँ हैं जो आपराधिक मामलों का निर्णय करते समय ट्रायल कोर्ट को बाध्य नहीं करेंगी। तदनुसार आपराधिक अपीलों की अनुमति दी जाती है और उच्च न्यायालय के निर्णयों को रद्द कर दिया जाता है।

आर.पी.

अपील की अनुमति.

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' की सहायता से अनुवादक न्यायिक अधिकारी राहुल शर्मा (आर.जे.एस.) द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण: यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही प्रामाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।